VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
MN No. 3
22 OCT 2016
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 754)

Name of Candidate	P. Yadav		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	23965
Center	MN	Date	22/10/16.

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH.
   इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

75, 3rd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Near Axis Bank, New Delhi – 110060

103, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi – 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks.

12.5X20=250

1. The Brussels Summit succeeded in rebooting the EU-India strategic partnership, though it did not see the closing of gaps between the two sides. Discuss.

ब्रसेल्स शिखर सम्मलेन ई.यू. तथा भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी की पुनः शुरुआत (रीबूट) करने में सफल रहा, यद्यपि इससे दोनों पक्षों के बीच के मतभेदों को पाटना संभव नहीं हो पाया। चर्चा कीजिए।

बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में ई.यू. व भारत का शिखर सम्मेलन कुछ प्रगतिशील कदमों को लेकर संपन्न हुआ। यह सम्मेलन भारत व यूरोपियन संघ के बीच 'व्यापक आर्थिक व निवेश समझौते' हेतु दोनों के बीच जारी वार्ता का परिणाम था।

हालांकि इस सम्मेलन में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, तथापि परिणामों के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।

रणनीतिक साझेदारी की पुनः शुरुआत:

→ दोनों पक्षों ने एक दूसरे के हितों के मद्देनजर संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक संयुक्त मंच के माध्यम से विभिन्न वार्ता से यथासंभव पारस्परिक शंकाओं को सुलझाएंगे।

→ वैश्विक मुद्दों पर भारत व EU दोनों एक-दूसरे

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

को पर्याप्त सहयोग देंगे।

⇒ यूरोपियन यूनियन आतंकवाद पर UN में भारत द्वारा प्रस्तावित व्यापक आतंकवाद निरोधक समझौते का समर्थन करेगा।

⇒ वार्षिक नौसैनिक स्थल सेना के साथ-साथ वायु सेना अभ्यासों द्वारा अपनी सामरिक सहयोग बढ़ायेंगे।

⇒ साथ ही, EU द्वारा TPP के तहत आर्थिक व सामरिक प्रभाव बढ़ाने के आलोक में अब भारत व EU दोनों ने परस्पर सहयोग की वकालत की।

⇒ मध्य एशिया की अशांत स्थिति के आलोक में यूरोपियन यूनियन को भारत की ओर ध्यान बढ़ाता है।

⇒ मुक्त व्यापार समझौते के मार्ग में आने वाली बाधाओं को यथाशीघ्र सुलझाने पर सहमति।

लेकिन फिर भी दोनों देशों के मध्य अभी भी कई मुद्दे हैं जिन पर आम सहमति का अभाव है —

मतभेद के मुद्दे

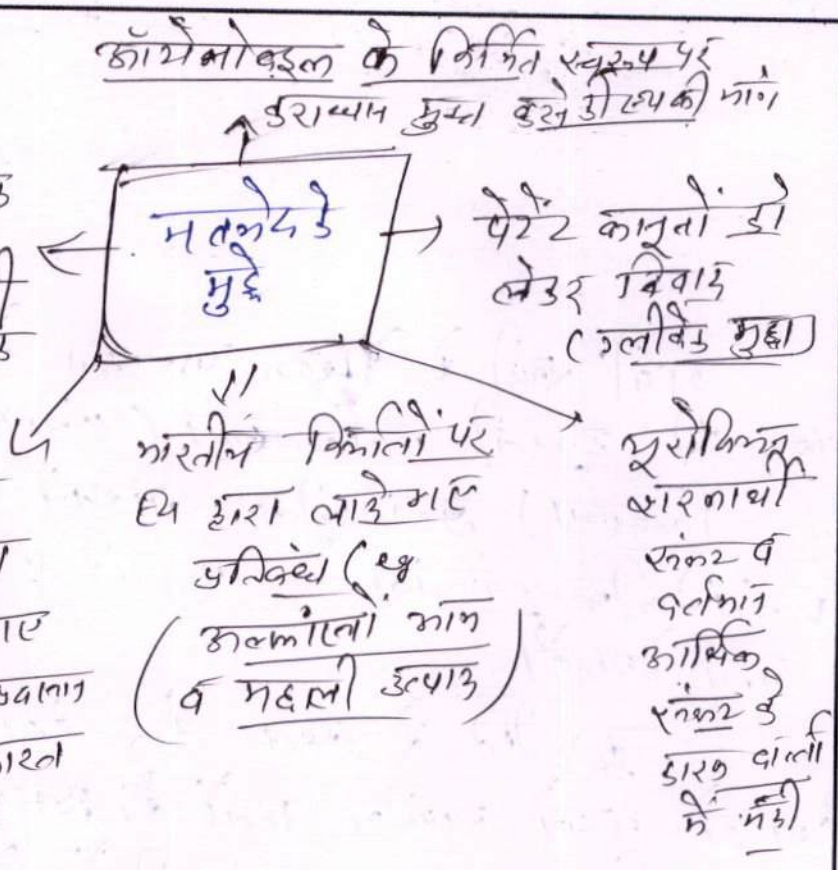

- ऑटोमोबाइल के निर्मित स्वरूप पर आयात शुल्क कम करने की मांग
- पेटेंट कानूनों को लेकर विवाद (जेनेरिक मुद्दा)
- एल्कोहॉलिक पेयों पर भारत द्वारा भारी आयात शुल्क का मुद्दा
- भारतीय निर्यातों पर EU द्वारा लगाए गए प्रतिबंध (जैसे अल्फांसो आम व मछली उत्पाद)
- EU के कुछ देशों यथा ब्रिटेन द्वारा लाए गए नए आव्रजन कानून से भारत की चिंताएं
- यूरोजोन सरकारी संकट व वर्तमान आर्थिक संकट के कारण वार्ता में मंदी

फिर भी प्रत्येक सम्मेलन संबंधों के पुनर्मूल्यांकन में एक क्रांतिकारी कदम है। दोनों भागों में सक्रियता से संबंधों को आगे बढ़ाने व आपसी विवादों/मतभेदों को पारस्परिक वार्ता से यथाशीघ्र निपटाने पर प्रतिबद्धता जाहिर की है। कई वर्षों से लंबित वार्ता की पुनः शुरुआत एक अच्छा कदम है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. While India has taken excellent steps towards utilization of space for diplomacy, there still seems to be a lot of room for exploiting our capabilities for regional and global diplomacy. Elaborate citing examples.

यद्यपि भारत ने कूटनीतिक अवसरों के उपयोग के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए हैं, इसके बावजूद क्षेत्रीय तथा वैश्विक कूटनीति के लिए हमारी क्षमताओं के पूर्ण दोहन के लिए अतिरिक्त स्थान शेष हैं। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सविस्तार समझाईये।

21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य में भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था (सबसे तेजी की अर्थव्यवस्था) प्रगतिशील लोकतंत्र व महत्वाकांक्षी लोगों के साथ आगे बढ़ने वाला देश है।

कूटनीति के तहत कोई देश अन्य देश को अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए वार्ता व अन्य कूटनीतिक तरीकों से प्रभावित करता है इससे दोनों देशों को प्रत्यक्ष हानि भी नहीं होती है।

भारत ने अपने बढ़ते वैश्विक प्रभावों के तहत कूटनीति अवसरों का भरपूर फायदा उठाने का प्रयास किया है। यथा: [illegible] शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पोषित करने वाले राष्ट्रों के खिलाफ जिम्मेदारी राष्ट्रों को एकजुट किया। इसी तरह ही कूटनीति का प्रयोग भारत में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने का सफल प्रयास किया।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

कूटनीतिक अवसरों का लाभ उठाकर ही भारत ने SCO में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अमेरिका के साथ 'रक्षा सहयोगी का दर्जा' प्राप्त करना भी भारत की कूटनीतिक सफलता का परिणाम है।

क्षेत्रीय स्तर पर कूटनीति

सफल प्रयोग

→ 'पड़ोसी प्रथम' नीति के तहत द० एशियाई देशों से संबंध सुधार eg - नेपाल को सहायता

→ क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रगतिशील वार्ता (अफगानिस्तान से लेकर)

→ सार्क के तहत सहयोग बढ़ाना (सार्क उपग्रह)

→ चीनी प्रभाव को संतुलित करने हेतु 'मौसम' प्रोजेक्ट व सागर परियोजना की तकनीक

→ AIIB व NDB में सक्रिय भागीदारी

दोहन का अतिरिक्त स्थान

→ सार्क के तहत सामर्थ्य का पूर्ण दोहन न कर पाना

→ आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा पर क्षेत्रीय तंत्र का नाकामी

→ अंतरिक्ष व तकनीक क्षमता का पूर्ण दोहन न कर पाना

→ पाकिस्तान के साथ संबंध को बहुआयामी न बना पाना

→ श्रीलंका, म्यांमार (रोहिंग्या) मुद्दों पर सफल कूटनीति नहीं

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

वैश्विक कूटनीति

सफल प्रयोग

→ पेरिस सम्मेलन में ग्लोबल स्तर पर प्रतिबद्धता योगदान को स्वीकार करवाना

→ पहली बार UN में सुधार के प्रस्ताव को अनुमोदित करवाना

- MTCR की सदस्यता प्राप्त करना

→ BRICS के तहत बहुध्रुवीयता को बढ़ावा

→ IMF व WB स्तर पर एकाधिकारता को कम करने के उपाय में AIIB

प्रयास बाकी

→ आतंकवाद निरोध सम्मेलनों पर पर्याप्त सफलता न मिलना

→ सीरिया, इराक, ISIS जैसे मुद्दों पर भारत का स्वतंत्र स्वरूप व प्रभावी कदम न उठाना

→ भारतीय समाज पर स्वीकृति का अभाव

→ धार्मिक कट्टरवाद को रोकने में पर्याप्त सफलता न मिलना

भारत को यदि वैश्विक कूटनीति में अपना प्रभावी कदम रखना है तो जो भी कूटनीतिक अवसर भारत को मिले उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए तथा अपनी शांतिप्रियता, लोकतांत्रिक मूल्यों व आर्थिक भूमिका का प्रभावी प्रस्तुतिकरण करें।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Much ground needs to be covered before BIMSTEC can emerge as a political game changer for the North Eastern region's overall development as well as a pertinent link in the Act East Chain. Discuss.

बिम्सटेक (BIMSTEC) के पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु एक राजनीतिक दिशा-परिवर्तक के साथ-साथ एक्ट ईस्ट श्रृंखला में एक उपयुक्त कड़ी के रूप में उभरने से पूर्व बहुत कुछ किया जाना अभी शेष है। चर्चा कीजिए।

बिम्सटेक, 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलोजिकल व इकॉनोमिक कॉर्पोरेशन', दक्षिण एशिया के देशों नेपाल, भूटान, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका व थाईलैंड (7) के मध्य आर्थिक व प्रौद्योगिकीय पहल के रूप में 1997 में शुरू किया गया।

वर्तमान में जब क्षेत्रीय सहयोग संगठनों की महत्ता फिर से प्रबल होती जा रही है (TPP के आलोक में)। ऐसे में बिम्सटेक अपार संभावनाओं को दर्शाता है।

बिम्सटेक के मंत्रियों के एक शिखर सम्मेलन में दिल्ली में आपसी सहयोग के एक नये प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। साथ ही, बिम्सटेक एक अधिक स्थायी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाला व उभरती अर्थव्यवस्थाओं (भारत, थाईलैंड, श्रीलंका इत्यादि) का देश है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इससे अफगानिस्तान व भारत के बीच के खाली स्थान को भरा है और इस प्रकार से स्नाई (चपार व अफगा होउजर) व अफगानिस्तान का लिंक है। इससे राजनीतिक महत्व के तहत आपसी सहयोग को बढ़ाता है।

विस्तारित - संभावना

उत्तर पूर्व विकास

- भारत के इस स्थल आबद्ध भाग को समुद्री पहुँच दिलाना - सितवे व चटगाँव पोर्ट
- स्थानीय उत्पादों हेतु बाजार उपलब्धता (म्यांमार, बांग्लादेश)
- परिवहन व्यवस्था का जुड़ाव
- शांति व उग्रवाद पर रोक (बांग्लादेश से प्रत्यर्पण संधि, म्यांमार द्वारा सहयोग)
- अवैध प्रवास पर रोक (भारत BD भूमि समझौता) व

एक्ट ईस्ट नीति

(शृंखला)

- म्यांमार व थाईलैंड आसियान राष्ट्र
- ASEAN तक पहुँच बढ़ाना - भारत - म्यांमार - थाईलैंड कॉरिडोर
- कालादान प्रोजेक्ट
- सांस्कृतिक जुड़ाव (बौद्ध धर्म अनुयायी) नालंदा विश्वविद्यालय
- हिन्द महासागर में प्रभावी भूमिका
- भारत हेतु पारगमन सुविधा (म्यांमार थाईलैंड)
- आर्थिक व रणनीतिक सहयोग (चीन को प्रति संतुलित करना) व

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

तमाम सम्भावनाओं के बावजूद अनेक चुनौतियों का समाधान हेतु प्रयास किए जाने आवश्यक हैं।

चुनौतियाँ	प्रयास
(1) पारस्परिक जुड़ाव की कमी	→ भौतिक जुड़ाव हेतु ट्रक - कालादान मल्टी मोड परियोजना, भारत म्यांमार, बांग्लादेश नेपाल कॉरिडोर - अजस्व यूरोप नगरिक हाइवे।
⇒ आर्थिक संबंधों में ठहराव	→ फिर से बढ़ाने हेतु मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर वार्ता - लाइन ऑफ क्रेडिट (बांग्लादेश, म्यांमार)
⇒ उग्रवादी गतिविधियों पर रोक	→ प्रत्यर्पण संधि (म्यांमार, थाईलैंड) तथा आसूचना साझा करना
⇒ सांस्कृतिक व विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग	→ बुद्धिस्ट आयोजन, भारत द्वारा उपलब्ध सुविधाएं (eg. IRNSS)

बिम्सटेक की बढ़ती भूमिका हाल ही में इसका ब्रिक्स के साथ सम्मेलन व वार्ता आयोजन से देखा जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Relations with Iran hold a lot of potential for India's ambitions for West Asia and beyond, however, realising this potential also involves certain global and regional challenges. Examine.

ईरान के साथ संबंध वस्तुतः पश्चिम एशिया और उससे परे भारत की महत्वाकांक्षा के लिए संभावनाओं से परिपूर्ण हैं, तथापि इस संभावना को साकार करने के मार्ग में कुछ वैश्विक तथा क्षेत्रीय चुनौतियां भी हैं। परीक्षण कीजिए।

ईरान - भारत संबंध ऐतिहासिक काल से काफी मजबूत व बहुआयामी (आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक) इत्यादि रहे हैं। वर्तमान में भी भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का एक बड़ा भाग (पेट्रोलियम के रूप में) ईरान से प्राप्त करता है तो बदले में ईरान भी फार्मास्यूटिकल, खाद्यान्न, बैंकिंग, फिल्मांतरी उत्पादों हेतु भारत पर निर्भर है।

ईरान के साथ भारत के संबंध रणनीतिक आधार पर भी काफी महत्वपूर्ण है जो ईरान की भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक महत्त्व, राजनीतिक व्यवहार, सामरिक हित व सुरक्षा के आलोक में महत्वपूर्ण है।

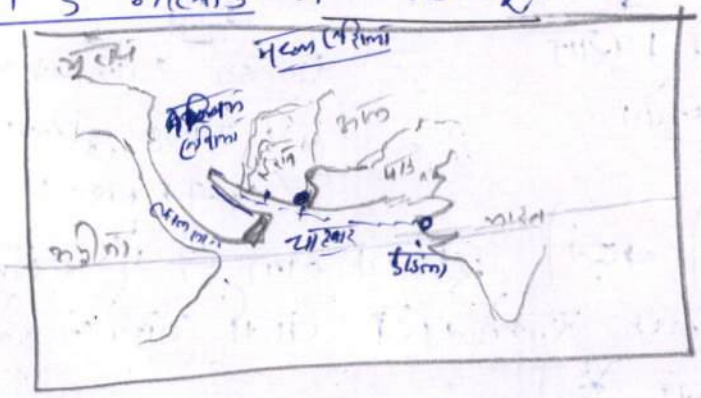

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संबंधों के द्वारा संभावित लाभ

→ भारत की पहुंच मध्य एशिया व पश्चिम तक सुनिश्चित करना (चाबहार पोर्ट विकास)

→ पश्चिम एशिया में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों की सुरक्षा हेतु उचित सहयोग देना (सुरक्षा - ISIS, स्थानीय अशान्ति इत्यादि)

→ मध्य एशिया के ऊर्जा संसाधनों तक भारत की पहुंच सुनिश्चित करना (तेल, गैस इत्यादि)

→ आतंकवाद व धार्मिक कट्टरवाद (सीरिया, इराक) पर भारतीय रणनीति हेतु ईरान सहयोग आवश्यक

→ पश्चिम एशिया के साथ भारत के सुरक्षित व्यापार को बढ़ाने हेतु सामुद्रिक सहयोग करना (अरब की खाड़ी क्षेत्र में

→ वैश्विक शांति बढ़ाने तथा पश्चिमी ताकतों के प्रभाव को कम संतुलित करने में (सहयोगी)

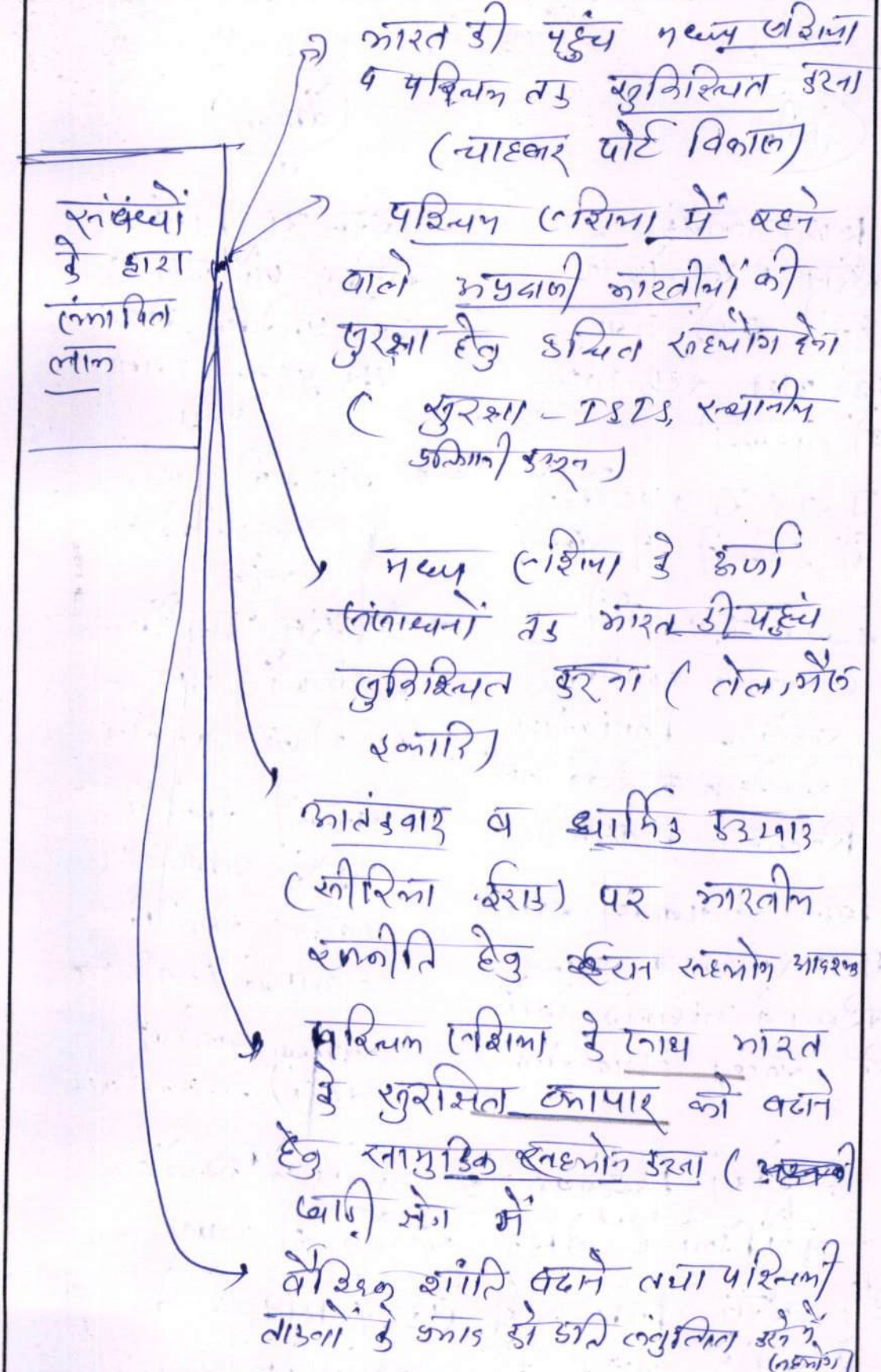

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ

क्षेत्रीय

- शिया समर्थक ईरान के सहयोग से सुन्नी राष्ट्रों यथा सऊदी अरब, कतर आदि में नाराजगी
- ISIS का प्रभाव रोकने में ईरान की भी नाकामी
- ईरान में बढ़ता चीनी प्रभाव (सामरिक राजनीतिक सहयोग - शिनजियांग से तेहरान तक रेलवे मार्ग सिल्क रूट के तहत)
- शिया मतावलंबी ईरान का पश्चिम एशिया व मध्य एशिया के अधिकांश देशों से संबंध खराब होना

वैश्विक

- ईरान का विवादित परमाणु कार्यक्रम और उस पर लगे प्रतिबंध को अभी तक पूर्णतः न हटाया जाना
- भारत की परमाणु अप्रसार नीति का उल्लंघन
- ईरान द्वारा वैश्विक संगठनों, NPT इत्यादि की सदस्यता न लेना
- पश्चिमी राष्ट्रों के आर्थिक प्रतिबंधों से अस्थिर राजनीतिक व आर्थिक स्थिति
- सामुद्रिक प्रायोजित (डकैती) उत्पन्न की चुनौती

उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में निस्संदेह चुनौतियाँ हैं लेकिन सहयोग की अपार संभावना है। ईरान विश्वसनीय एवं सुरक्षित गेटवे के रूप में भारत को सहयोग दे सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. While India isn't a party to the South China Sea dispute, it needs to take keen interest in the region as a part of its commitment towards the "Act East Policy". Comment.

यद्यपि भारत दक्षिण चीन सागर विवाद का पक्षकार नहीं है, फिर भी इसे "एक्ट ईस्ट नीति" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण इस क्षेत्र में गहरी रूचि लेने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के एक भाग के रूप में चीन, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया इत्यादि देशों से घिरा हुआ है। इतने देशों के नजदीकी होने से इनके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को लेकर तथा विभिन्न द्वीपों पर ऐतिहासिक संप्रभु अधिकार को लेकर संबंधित देशों में विवाद है।

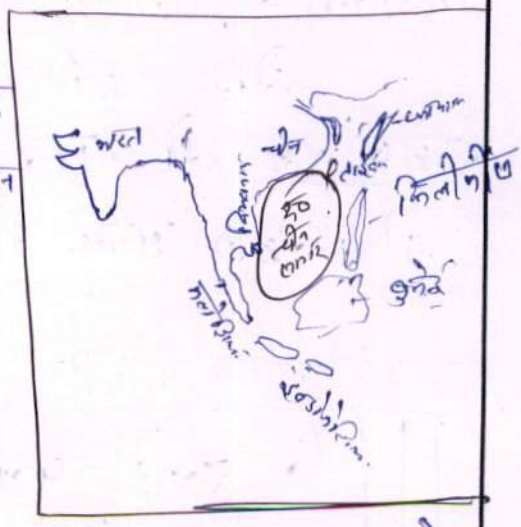

जहाँ चीन संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दावा करता है, वहीं फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया इत्यादि के भी अपने स्वशासन अधिकार हैं।

यद्यपि भारत इस क्षेत्र से भौगोलिक संबंध व सामीप्य नहीं रखता है लेकिन अनेक कारणों से यह भारत हेतु महत्वपूर्ण है और विशेष एक्ट ईस्ट पॉलिसी हेतु।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

'एक्ट ईस्ट नीति' के तहत दक्षिण पूर्व एशिया व पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को बहुआयामी पक्षों के साथ व्यावहारिक धरातल पर लाना चाहता है। और

लेकिन यदि इस क्षेत्र में अशांति व संघर्ष रहा तो भारत की महत्वाकांक्षाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारत की रुचि क्यों?

- इसके पश्चात भारत की एक्ट ईस्ट नीति के भागीदार राष्ट्र
- इस क्षेत्र 5.3 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक व्यापार होता है इसलिए अशांति भारतीय हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- यहां पर भारत वियतनाम के साथ संयुक्त समुद्रिक खनन गतिविधियों में लगा हुआ है। संघर्ष भारतीय निवेश पर चिंता बढ़ाएगा।
- विवाद में अधिकांश आसियान देश सम्मिलित होने से भारत - आसियान व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ भारत के उत्तर पूर्व के विकास को भी बाधित करेगा।

↳ भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

↳ RCEP जैसे क्षेत्रीय समझौतों के लागू होने में बाधक बन सकता है।

भौगोलिक समीपता न होने के बावजूद भी भारत के अनेक सामरिक एवं राजनीतिक वहां पर निहित हैं। साथ ही भारत वैश्विक / अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का पक्षकार होने के साथ-साथ एक वैश्विक शक्ति की भूमिका में उभर रहा है। ऐसे में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफलता के साथ-साथ वृहद वैश्विक हितों के संदर्भ में भी भारत की गहन रुचि आवश्यक है। यद्यपि कई चुनौतियां विद्यमान हैं, परन्तु सक्रियता जरूरी है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. The internal crisis in Nepal over the past few years has given concrete shape to the fears of China gaining upper hand vis-a-vis a traditionally influential India. Elaborate. What can India do to further strengthen its ties with the Himalayan nation?

पिछले कुछ वर्षों में नेपाल के आतंरिक संकट ने पारंपरिक रूप से प्रभाव रखने वाले भारत पर चीन द्वारा बढ़त लिए जाने के भय को ठोस आकार प्रदान किया है। विस्तारपूर्वक बताईए। इस हिमालयी राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को अधिक मजबूत करने हेतु भारत और क्या कर सकता है?

आज़ादी के बाद से ही भारत नेपाल संबंध काफी सहयोगी व निर्भरता वाले रहे हैं। 'मित्रता संधि' के तहत भारत ने हमेशा नेपाली हितों का संरक्षण किया है (पारगमन सुविधा, मुक्त आवागमन, आर्थिक सहयोग इत्यादि)।

लेकिन हाल ही में नेपाल एक संवैधानिक संकट के दौर से गुजर रहा है। राजशाही के अंत (2007) के बाद से ही एक सर्वसम्मत संविधान की तैयारी पर विभिन्न दलों में मतभेद रहे। अंततः संविधान बना लेकिन नेपाल के दक्षिणी मधेशी व थारु (दोनों लगभग 50%) जाति के लोग उसके कुछ प्रावधानों - यथा: राज्यों का सीमांकन, सीट आवंटन, विवाह संबंध इत्यादि को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

उपरोक्त आंतरिक संकट के कारण भारत की ओर से भी भेजे जाने वाले तेल व खाद्यान्न ट्रकों को सीमा पर ही रुक जाना पड़ रहा है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

और नेपाली जनता को आवश्यक वस्तुओं की को सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि भारत ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया बल्कि यह उनके आंतरिक संकट के कारण हुआ है तथापि भारत विरोधी दल व राजनेता इसे जनता को भारत के खिलाफ करने में एक राजनीतिक हथियार के रूप में देख रहे हैं।

माओवादी सरकार ने चीन से इस संबंध में नजदीकी बढ़ाई है -

=) पट्रोलियम व खाद्य पदार्थों की आपूर्ति चीन द्वारा करवाना

→ चीन को हिमालयी तिब्बत के रास्ते नेपाली सीमा तक रेल / सड़क मार्ग स्थापना की अनुमति देना

→ चीन द्वारा भी नेपाल को अपने गुआन प्रांत के द्वारा समुद्र तक पहुंच देने का वादा करना।

→ चीन द्वारा नेपाल को अवसंरचना विकास में अधिक निवेश का आश्वासन देना।

→ नेपाली राष्ट्रपति की चीनी यात्रा।

→ तिब्बत के लोगों द्वारा नेपाल को सिक्कम जैसा न दिखाना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निस्संदेह तमाम कारण भारत को 'चीनी कार्ड' दिखाने की तरह हैं। नेपाल भारत पर अपनी आत्मनिर्भरता कम करना चाहता है तथा चीनी लोकलुभावने वादों से प्रभावित होकर जनता का विश्वास जीतना चाहता है।

लेकिन वह भारत को सिरे से नकार नहीं सकता है। क्योंकि अभी भी लगभग 60 लाख नेपाली भारत में रहते व रोजगार करते हैं और व्यापक आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध विद्यमान हैं।

भारत क्या कर सकता है -

↳ भारत उनके आंतरिक विवाद समाधान हेतु विशेषज्ञ सहयोग दे।
↳ जनता को विश्वास दिलायें कि भारत हमेशा उनके हित में है - सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा
↳ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करते रहें।
→ नेपाल में भारतीय निवेश को बढ़ाने का प्रयास करें।
→ लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ-साथ आधारभूत विकास करना, ICT सेवायें उपलब्ध कराना।

भारत अपनी भौगोलिक समीपता व सांस्कृतिक संबंधों का फायदा उठाकर तथा भूकंप पीड़ित नेपाल के पुनर्निर्माण में सहयोग कर चीनी प्रभाव को प्रतिसंतुलित कर सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. A nation's foreign policy is strongly influenced by the imperatives of its strategic environment, its neighbourhood and its status in the international community. Elaborate with respect to the evolution of India's foreign policy.

किसी देश की विदेश नीति दृढ़ता से उसके सामरिक परिवेश की आवश्यकताओं, उसके पड़ोसी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच उसकी हैसियत से प्रभावित होती है। भारत की विदेश नीति के विकास के सन्दर्भ में इसक कथन की सविस्तार व्याख्या कीजिए।

विदेश नीति किसी राष्ट्र के उन मूल्यों व सिद्धान्तों को प्रतिपादित करती है जो कोई राष्ट्र अन्य किसी राष्ट्र के साथ संबंध बनाने व वैश्विक विषयों पर अपनी संलग्नता के दौरान अनुपालन करता है।

विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक -

- भौगोलिक अवस्थिति - (रणनीतिक स्थिति)
- ऐतिहासिक अनुभव (उपनिवेशवाद व पीड़ित)
- राजनीतिक व्यवस्था (eg लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान)
- सांस्कृतिक विविधता (eg. सहिष्णुता
- राजनीतिक स्थिति (eg. ईरान की अवस्थिति युक्त (नई) मार्ग पर)
- राष्ट्रीय मूल्य - (eg भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अवधारित)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारतीय विदेश नीति के सिद्धान्त

- पंचशील का सिद्धान्त
- गुटनिरपेक्षता
- रंगभेद, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध
- सतत् विकास व पारस्परिक संपर्क
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का सम्मान इत्यादि

किसी भी देश की विदेशनीति पर उसकी सामरिक अवस्थिति काफी प्रभाव डालती है ताकि वह अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके तथा अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ा सके। उदाहरण के लिए भारत ने हाल ही हिन्दमहासागरीय देशों के साथ सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध बढ़ाने का प्रयास किया है जो इस क्षेत्र चीनी प्रभाव को प्रति संतुलित करें।

पड़ोसियों के साथ विदेशनीति का अहम भूमिका हमेशा पारस्परिक विश्वास व साझा हितों पर होनी आवश्यक है। क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था —

"हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं।"

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

इसी आलोक में भारत ने अपने बड़े भाई की भूमिका को पड़ोसियों के हित में लगाया। गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत जहां पड़ोसियों को उदारता सहयोग नीति अपनायी, वहीं वर्तमान में हमने 'पड़ोसी प्रथम' व 'साझा विकास' की रणनीति अपनायी है। ऐसा करना भारत की एक क्षेत्र में मजबूत राष्ट्र होने के नाते आर्थिक आवश्यकता व नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है।

इसी तरीके अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भी आपकी हैसियत से विदेशनीति निर्धारित होती है। चाहे वो भारत के अमेरिका से रक्षा संबंध, चाहे जलवायु परिवर्तन पर पेरिस वार्ता, या फिर सीरिया मुद्दे पर वोटिंग इत्यादि सब जगह भारत की हैसियत ने प्रभावित किया।

लेकिन, यह सही है कि आपकी हैसियत व सामरिक स्थिति प्रभावित करती है लेकिन विदेश नीति इससे भी बढ़कर सिद्धांतों व मूल्यों पर आधारित होती है जो अपने मूल को नहीं छोड़ती है। मानवाधिकार, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पारस्परिक सद्भाव, निरस्त्रीकरण, वैश्विक हित इत्यादि आज भी भारतीय विदेश नीति के मूलाधार हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Signing of Logistical Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) with USA has signalled a change in India's policy towards its neighbours especially China. What can be the possible implications of such a policy? Can it be a counter-productive move?

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लॉजिस्टिकल एक्सचेंज मेमोरैन्डम ऑफ एग्रीमेंट (एल.ई.एम.ओ.ए.) पर हस्ताक्षर करना भारत द्वारा अपने पड़ोसियों, विशिष्ट रूप से चीन के साथ अपनाई जाने वाली नीतियों में परिवर्तन का एक संकेतक है। ऐसी नीति के क्या संभव निहितार्थ हो सकते हैं? क्या यह एक प्रति-उत्पादात्मक कदम सिद्ध हो सकता है?

USA के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक व रक्षा संबंधों का ही परिणाम है कि USA ने भारत को "रक्षा सहयोगी राष्ट्र" का दर्जा दिया है। इस दिशा में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी एक प्रगतिशील पहल है। लेमोआ (LEMOA) के तहत दोनों देश —

- एक दूसरे के सैन्य बेस का इस्तेमाल ईंधन भरने, रुकने के लिए कर सकते हैं
- दोनों सेनाएँ आपदा, संकट में पर्याप्त सूचनाएँ व उपकरण सहयोग एक दूसरे को प्रदान करेंगी
- वार्षिक रक्षा अभ्यास में एक दूसरे के प्रशिक्षक सहयोग प्रदान करेंगी।

भारत अमेरिका सहयोग के इस रोल को एक क्रांतिकारी व प्रगाढ़ कदम माना जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चीन की बढ़ती सक्रियता (सिल्क रोड मार्ग, वन बेल्ट वन रोड, इत्यादि) के कारण हिन्द महासागर व दक्षिण चीन सागर में भारत (विशेषरूप से) तथा अमेरिका (अप्रत्यक्ष रूप से) के हितों पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रतिक्रिया में सम्पन्न एक दूरगामी समझौता है। यह भारत की नीति में परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है कि अब भारत अपने हितों की रक्षा के लिए बाह्य ताकतों का सहयोग भी ले सकता है।

लेकिन यह एकतरफा विचार है वास्तव में ऐसी नीति के अन्य निहितार्थ भी हैं।

- दोनों देशों ने केवल सामान्य सुविधाओं देने पर बातचीत की है, ना कि सैन्य सहयोग।
- यह केवल आपदा राहत, बचाव व अन्य आपदा जैसे संकट में त्वरित सहयोग का परिणाम है।
- भारत व पड़ोस अपने व्यापार व रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
- एक व्यापक सुरक्षा सहयोग सामुद्रिक पायरेसी रोकने में भी सहयोगी होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

यह डील नुकसानदायक कदम भी हो सकता है-

↳ हिन्द महासागरीय क्षेत्र में USA की उपस्थिति। यह दीर्घकाल में भारतीय हितों के प्रतिकूल।

↳ इससे USA भारत की रक्षा तैयारियों व रक्षा सामग्री की सघन ही जानकारी ले पायेगा

↳ किसी संघर्ष की स्थिति में भारत पर नैतिक दबाव देने का दबाव डाल सकता है।

↳ चीन आदि देशों को अधिक आक्रामक बना सकता है।

↳ भारतीय विदेश नीति पर दबाव डाल सकता है

लेकिन तमाम विरोधाभासों व चिंताओं के बावजूद भी यह एक सकारात्मक कदम है तथा रक्षा सहयोग को बढ़ायेगा तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग करेगा।

बशर्ते भारत को और अधिक स्वतंत्रता व पारदर्शिता से नियमन करना चाहिए तथा आपात उपयोग अवस्था भी स्पष्ट होनी चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. The Trans-Pacific Partnership agreement (TPP), touted as the world's biggest trade deal to date, has danger of bending the WTO rules. In this context, discuss the impact TPP can have on India's foreign trade. What are the options that India has to deal with the issues arising out of the TPP?

विश्व के सबसे बड़े व्यापार समझौते के रूप में प्रचारित ट्रांस-पेसिफ़िक पार्टनरशिप (टी.पी.पी.) समझौते द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. के नियमों को प्रभावित करने की आशंका है। इस परिप्रेक्ष्य मे भारत के विदेश व्यापार पर टी.पी.पी. के संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिए। टी.पी.पी. से उत्पन्न मुद्दों से निपटने के लिए भारत के पास क्या विकल्प हैं?

ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप

प्रशांत महासागर के 12 देशों का एक व्यापक आर्थिक व व्यापारिक सहयोग समझौता है जो विश्व की लगभग 40% GDP व 45% आबादी वाले क्षेत्र को कवर करता है तथा उच्च मानकों पर आधारित सहयोग को बढ़ावा देता है। इसमें, आपसी व्यापार, पेटेंट कानून, श्रम कानूनों, पर्यावरणीय मानकों, गुणवत्ता मानक, सतत विकास इत्यादि उच्च मानकों व व्यापार स्तरों को अपनाया गया है।

जैसा कि स्पष्ट है कि कनाडा, USA, जापान इत्यादि राष्ट्र - WTO में भी अपनी प्रभावी भूमिका रखते हैं तथा विभिन्न

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मुद्दों पर कुछ लाभ बड़े नजर आते हैं। इस तरह में विशेष की से WTO की नीतियों को प्रभावित करने के प्रयास कर सकते हैं। TPP के संचालन के उपरांत प्रचलित उच्च मानकों व मूल्यों को ये WTO में भी शामिल करने पर दबाव डाल सकते हैं जो भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

भारतीय विदेश व्यापार पर TPP का प्रभाव

- भारत के वरीयता आधारित व्यापार क्षेत्र भारत से छिन सकते हैं।
- भारतीय निर्यातों की मांग इन देशों में यथा USA, जापान, वियतनाम इत्यादि में घटेगी।
- उच्च मानकों व अन्य मानकों के आधार पर भारतीय उत्पादों की बिक्री पर रोक लग सकती है।
- CEPA, FTA का प्रभाव (जापान) घट सकता है।
- भारत का चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा, और आयात को भी प्रभावित करेगा। Make-in-India जैसे विनिर्माण को हतोत्साहित।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ इन क्षेत्रों से भारत में आने वाले विदेशी निवेश में कमी आ सकती है। (FDI)

भारत के पास विकल्प

← TPP में शामिल होने का प्रयास करे

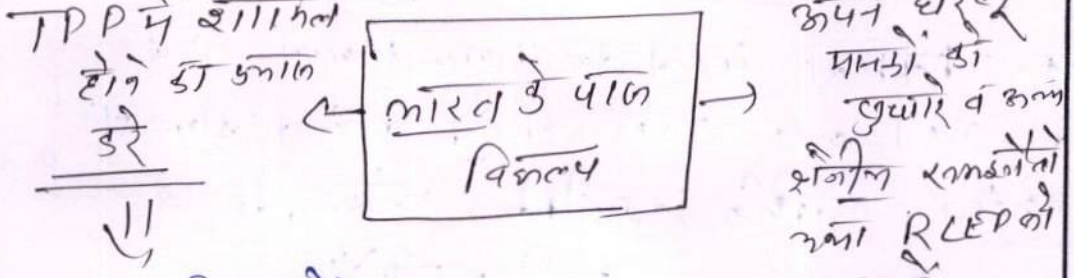

⇓

किन्तु भविष्य में यह संभावना कम ही है क्योंकि –

- भारत की भौगोलिक दूरी
- भारतीय उत्पादों की निम्न गुणवत्ता
- भारत अभी उन मानकों को अपनाने में सक्षम नहीं।

इत्यादि.

→ अपने घरेलू मानकों को सुधारें व अन्य क्षेत्रीय समझौतों यथा RCEP को बढ़ावे

⇓

- घरेलू स्तर पर धीरे धीरे मानकों को बढ़ाकर उत्पाद गुणवत्ता बढ़ाना
- बाजार विविधीकरण (व्यापार नीति 2015-20) अफ्रीका, लैटिन अमेरिका पर फोकस करना
- यूरोपियन यूनियन से भी मुक्त व्यापार समझौता करना
- RCEP जैसे बहुपक्षीय समझौतों को शीघ्र पूर्ण करना।
- अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से सहयोग बढ़ाना।

निष्कर्ष

भारत को सभी पक्षों से सभी आयामों को संतुलित करते हुए एक दूरदर्शी रणनीति बनानी चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Indo-Afghan relations go much beyond the Indo-Pakistan rivalry. Explain. In this context how significant is the Heart of Asia Conference?

भारत-अफगान संबंधों का दायरा वस्तुतः भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता से अधिक विस्तृत है। व्याख्या कीजिए। इस सन्दर्भ में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण है?

भारत - अफगानिस्तान के भारत से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। मुगलकाल से लेकर ब्रिटिश काल तक अफगानिस्तान भारत का बड़ा-सा भाग रहा है। भारत अफगान संबंध आर्थिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक व कूटनीतिक स्तर पर काफी अच्छे हैं।

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अफ-भारत संबंध भारत-पाक प्रतिद्वंद्विता से ही उत्पन्न है।

↳ भारत पाक का घेराव करना चाहता है।

↳ पाकिस्तान की आतंकी समूहों तक पहुंच व सहयोग खत्म करने के आलोक में

↳ कश्मीर में सुरक्षा हेतु अफगानिस्तान की भौगोलिक अवस्थिति का लाभ उठाना।

↳ पाकिस्तान को अलग-थलग करने हेतु

लेकिन भारत अफगानिस्तान संबंधों का दायरा काफी व्यापक है -

अफ़ भारत संबंध

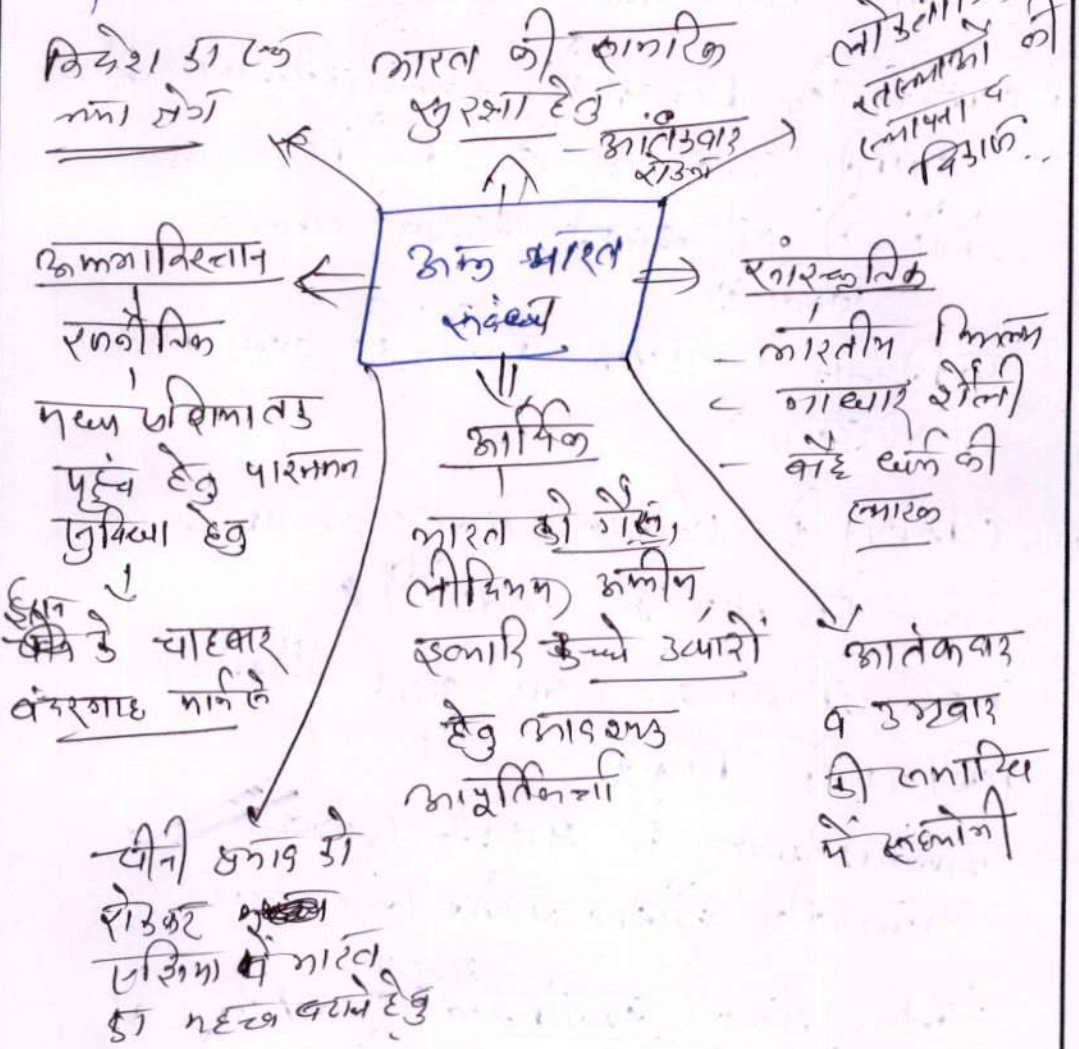

- भारत की सामरिक सुरक्षा हेतु - आतंकवाद रोकना
- विदेश व्यापार नया रास्ता
- लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना व विकास..
- अफगानिस्तान
  - राजनीतिक
  - मध्य एशिया तक पहुंच हेतु पारगमन सुविधा हेतु
  - ईरान के चाबहार बंदरगाह मार्ग से
- सांस्कृतिक
  - भारतीय मिशन
  - गांधार शैली
  - बौद्ध धर्म की स्मारक
- आर्थिक
  - भारत को गैस, लौहिकम खनिज इत्यादि कच्चे उत्पादों हेतु आवश्यक आपूर्तियाँ
- आतंकवाद व उग्रवाद की समाप्ति में सहयोगी
- चीनी प्रभाव को रोककर एशिया में भारत का महत्व बढ़ाने हेतु

इस संदर्भ में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध हो सकता है क्योंकि -

→ यह अफगानिस्तान का एक स्थायी समाधान चाहता है जो यहां पर स्थायित्व हेतु आवश्यक।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ आतंकवाद को रोकने में वैश्विक पहल तथा क्षेत्र में शांति की रहे।

— एशिया के विकास में अफगानिस्तान की शांति आवश्यक है क्योंकि उससे क्षेत्रों में भी शांति संघर्ष खत्म रह सकती है।

— पाकिस्तान के नापाक कामों को प्रश्रय मिलना बंद होगा।

→ एशिया के एकीकरण हेतु अफगानिस्तान एक केंद्र बिंदु बन सकता है।

— मध्य एशिया को बढ़ावा मिलेगी तो पूर्व एशिया को विकास

— अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों व जनजातीय कौशल का दोहन संभव होगा।

लेकिन प्रभावी रणनीति [illegible] तथा व्यावहारिकता की अनुपस्थिति ने अभी भी यह सम्मेलन को अप्रभावी बनाये हुए है रखा है, कुछ राष्ट्र नहीं चाहते कि अफगानिस्तान शांत रहे क्योंकि यह उनके हितों के प्रतिकूल है। इसलिए निष्पक्ष अफगानिस्तान की जनता व मानवता के लिए एक व्यापक रणनीति की तथा स्थायी समाधान हो।

11. In the recent times India has been considering a more comprehensive maritime policy in the Indian Ocean. What are the factors responsible for the recent push in this direction? How far is the Indian Ocean key to India's foray in the Indo-Pacific region?

पिछले कुछ समय से भारत हिन्द महासागर में एक अधिक व्यापक समुद्री नीति पर विचार करता रहा है। इस दिशा में झुकाव के लिए हाल के प्रयासों के लिए कौन-से कारक उत्तरदायी हैं? हिन्द महासागर किस सीमा तक इंडो-पेसिफ़िक (भारत-प्रशांत) क्षेत्र में भारत के प्रवेश की कुंजी है?

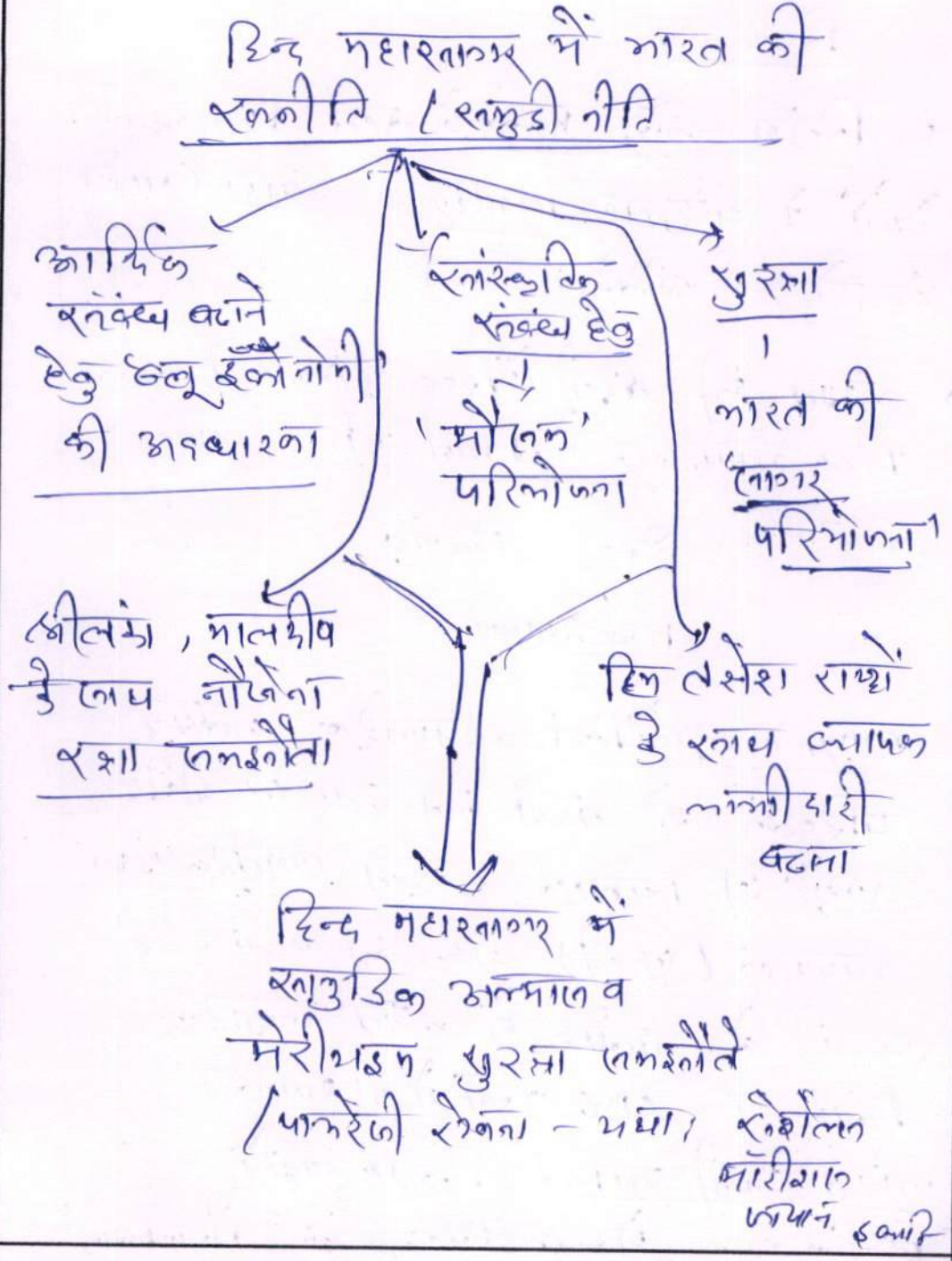

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इन मामलों हेतु भारी उत्तरदायी कारक

↳ चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' नीति के तहत विकसित किया जाने वाला मेरीटाइम सिल्क रूट

↳ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत हिन्द महासागरीय देशों के बंदरगाह विकास - ग्वादर (पाक) हंबनटोटा (श्रीलंका) इत्यादि

↳ भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका के कारण हिन्द महासागर में प्रभावी भूमिका आवश्यक

सिंगापुर

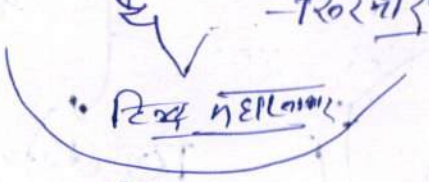

हिन्द महासागर

↳ सामुद्रिक चुनौतियाँ → प्राकृतिक, जलवायु परिवर्तन से बढ़ते जल स्तर से द्वीपीय राष्ट्रों की चिंताएं, बढ़ता समुद्री डकैती, आपदाएं (सुनामी) दोहन का बढ़ता स्तर इत्यादि के आलोक में सतत सामुद्रिक विकास (SDG लक्ष्यों में भी शामिल)

→ भारत अपनी आर्थिक क्रियाएं बढ़ाने (निर्यात बढ़ाने, मेड इन इंडिया कार्यक्रम, ब्लू इकोनॉमी)

- के लिए इस क्षेत्र की संभावनाओं को कायम रखना

- भारत को इस हिन्दमहासागर क्षेत्र बनाये रखने के लिए स्वाभाविक मित्रों की संख्या बढ़ाना तथा पारस्परिक विश्वास बढ़ाना

इंडो-पेसिफिक तक प्रवेश की कुंजी

↳ लगभग 50% कार्गो, 1/3 तेल आपूर्ति व 2/3 कच्चा माल इत्यादि की आपूर्ति का मार्ग

↳ अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की अवस्थिति से भारत को सामरिक हित

↳ भारत की हिन्दमहासागर में स्वाभाविक स्थिति भारतीय प्रभाव को बढ़ायेगी।

लेकिन यह एकमात्र कुंजी नहीं बल्कि हिन्द महासागरीय देशों के साथ भारत के संबंध हिन्द प्रशांत में भारत की भूमिका को बढ़ायेंगे साथ ही भारत की प्रशांतीय नीतियों की व्यापक भूमिका निभायेंगी

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. What are the reasons for the significance attached to India's relations with Myanmar? In what ways are the democratic changes in Myanmar going to affect these relations?

म्यांमार के साथ भारत के संबंधों को कौन-से कारक महत्वपूर्ण बनाते हैं? म्यांमार में हुए लोकतांत्रिक परिवर्तन किस प्रकार इन संबंधों को प्रभावित करेंगे?

भारत - म्यांमार संबंध में अनेक कारक उत्तरदायी .

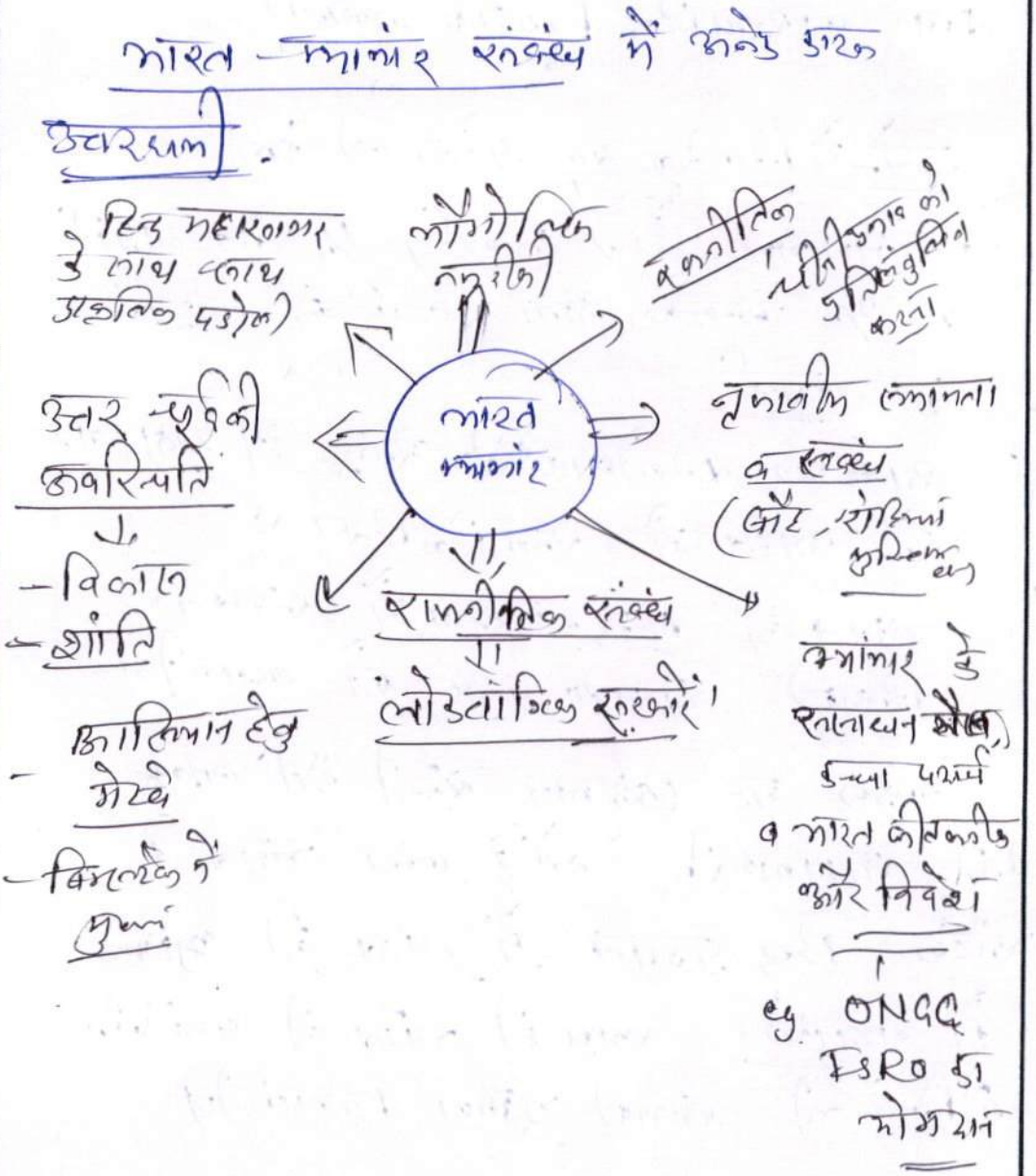

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लोकतांत्रिक परिवर्तन

↳ भारत के अब तक रहे वर्षों के संबंधों की दूरी को खत्म करेगा।

↳ राजनीतिक मूल्यों व संस्थाओं के विकास में भारत सहयोग कर पायेगा।

- संबंध यथार्थवाद की ओर बढ़ेंगे

↳ आर्थिक संबंध, विदेशी लाइन ऑफ क्रेडिट आदि के रूप में बढ़ेंगे।

↳ लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरा वैश्विक मुद्दों पर भारत को एक स्थायी सहयोगी देगा।

↳ भारतीय सुरक्षा के लिए स्वदेशकारी होने से उत्तर-पूर्व में शांति व विकास को बढ़ावा।

- नीतियों में स्थिरता से पारस्परिक वैज्ञानिक व औद्योगिकीय सहयोग बढ़ा सकेंगे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लेकिन कुछ चुनौतियाँ

- सेना की भारी की प्रभावी भूमिका का होना
- चीनी उपस्थिति से भारतीय हितों को प्रभावित कर सकती है।
- आंतरिक व नृजातीय संघर्ष की स्थिति
- अलगाववादी तत्वों को वहां पर प्रश्रय मिलना यथा NSCN - खापलांग।

फिर भी भारत को इस लोकतांत्रिक परिवर्तन का यदि लाभ उठाना है तो वहां लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करना होगा - प्रशासन, सहयोग, तकनीकी इत्यादि को तभी दोनों के हितों की सुरक्षा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Legal proceedings initiated by the Marshall Islands against India, Pakistan and Britain over nuclear weapons in the International Court of Justice highlights the issues of jurisidiction of the court. What is India's position vis-a-vis the jurisdiction of the ICJ? Also differentiate between binding and advisory pronouncements of the court with suitable examples.

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आई.सी.जे.) में मार्शल द्वीपसमूह द्वारा भारत, पाकिस्तान तथा ब्रिटेन के खिलाफ़ परमाणु हथियारों को ले कर आरम्भ की गयी कानूनी कार्यवाहियाँ वस्तुतः इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मुद्दे को उजागर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में भारत का क्या रुख है? साथ ही उचित उदहारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय के बाध्यकारी तथा सलाहकारी निर्णयों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

वैश्विक व द्विपक्षीय मुद्दों पर निर्णयन

क्षेत्राधिकार

बाध्यकारी | सलाहकारी

बाध्यकारी:
अपराधिक गतिविधियों
- सीमावर्ती बंटवारे
- अन्तर्राष्ट्रीय संधियों
(केवल सदस्य राष्ट्रों पर)

सलाहकारी:
- वैश्विक मुद्दों पर
- द्विपक्षीय हितों
- गैर सदस्यों को केवल सलाहकारी
तथा चीन द्वारा UNCLOS के उल्लंघन पर।

भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संगठन पर संतुष्ट है। उसका मानना है कि जिन मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता द्वारा हल हो सकता है, उनको इस न्यायालय में न ले जाया जाए।

- साथ ही वैश्विक महत्व वाले मुद्दों पर इसको निर्णयों को अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जाए। यथा: सामुद्रिक क़ानून, आतंकवाद रोधी क़ानून इत्यादि।

- इस न्यायालय को विभिन्न क्षेत्रीय तथा विधिक विशेषज्ञता आधारित होनी चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Discuss the causes and possible implications of UK exiting the European Union. Also assess the impact of such a scenario on India.

यूरोपीय संघ से यू.के. के अलग होने के कारणों तथा संभावित निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। साथ ही इस स्थिति में भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन कीजिए।

यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय राष्ट्रों एक यूनियन (आर्थिक) है जिसने सदस्य देशों की प्रशुल्क व गैर प्रशुल्क बाधाएं हटाकर एक साझा बाजार का रूप ले रखा है।

U.K. के अलग होने के कारण

- लगातार कुछ वर्षों से उत्पन्न यूरोपीय वित्तीय संकट
- यूरोप में बढ़ता शरणार्थी संकट और सदस्य देशों पर बढ़ता बोझ
- औद्योगिक विकास की धीमी गति के कारण बढ़ता संकट
- यूरोप में एक वर्ग द्वारा बढ़ती आलोचना तथा आर्थिक उदारवादी नीतियों पर इसका दुष्प्रभाव को मानना
- मुक्त श्रम व पूंजी की आवाजाही से ब्रिटेन में बढ़ती स्थानीय बेरोजगारी व तदुपरांत जनता असंतोष

↳ यूरोप के आव्रजन नियमों से ब्रिटेन की विमुखता

↳ यूरोपियन राष्ट्रों में बढ़ता असंतोष।

संभावित निहितार्थ

- बेहतर आर्थिक विकास की चाह
- द्विपक्षीय संबंधों के बढ़ते महत्त्व को बढ़ाना
- उदारवादी नीतियों से अर्जित आर्थिक हानि को रोकना
- स्वतंत्र विदेशनीति व आर्थिक नीति हेतु स्वतंत्र पहचान

ब्रिटेन हेतु

(−)

- संघ का महत्त्व घटना
- अलगाववाद की नयी धारा शुरू होना
- अर्थव्यवस्था को और हानि
- शरणार्थी संकट का गहराना (अल्पकाल)
- ब्रिटिश तकनीकों की मुक्त आवाजाही पर
- विदेशी मांग घट सकती है

यूरोपियन यूनियन

(+)

- कई विदेशी यूरोपियन में आ सकते हैं
- कर कानूनों के कारण कंपनियों का अन्य यूरोपियन देशों में जाना
- ब्रिटेन मसलन यूरोप की ओर आ सकता है का मोड़ आना
- ब्रिटेन के साथ अधिक लचीला रवैया अपनाना

etc

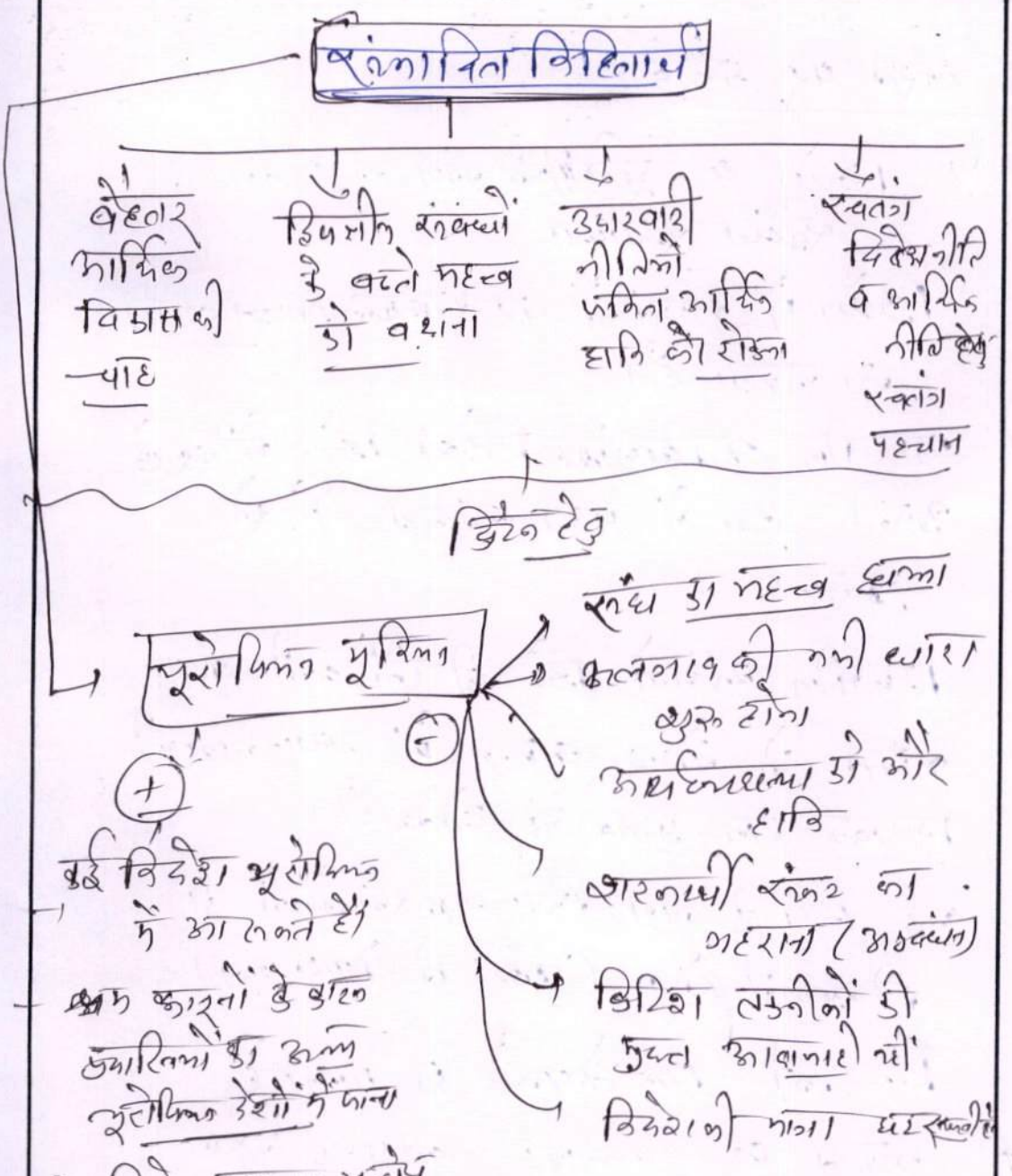

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत पर प्रभाव

↳ ब्रिटेन व यूरोपीय संघ से अलगाव संबंध स्थापना

ब्रिटेन में भारतीयों पर संरक्षण कानून लाया जा सकता है

↳ भारतीय अधिकांश निवेश ब्रिटेन में, इसके अलावा EU में पहुंच बाधित होने से नुकसान।

↳ द्विपक्षीय संबंधों ब्रिटेन की नौकरशाही बढ़ना

↳ भारत के शेयर बाजार में अचानक आयी गिरावट इसके प्रभाव का द्योतक है

↳ कई EU के साथ ब्रिटेन नए समझौतों का सिलसिला होगा (ब्रिटेन के दोबारा करना)

फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत का व्यापार फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि के साथ पहले ही काफी बढ़ चुका है तथा ब्रिटेन की भारत के प्रति उदार ही नीति अपनाएगा क्योंकि अब भारत बड़ा बाजार है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Even though the refugee crisis in Europe does not affect India directly, it presents an opportunity for India to showcase its commitment and capability to take greater responsibility in dealing with global issues. Comment in light of India's strengths, experience and international commitments regarding refugees.

यद्यपि, यूरोपीय शरणार्थी संकट का भारत पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, लेकिन यह भारत के लिए वैश्विक मुद्दों से निपटने हेतु अधिक बड़ी ज़िम्मेदारी ग्रहण करने संबंधी प्रतिबद्धता तथा क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। शरणार्थी संबंधी भारत के सामर्थ्य, अनुभव तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के आलोक में इस पर टिप्पणी कीजिए।

यूरोपीय शरणार्थी संकट मुख्यतः सीरिया व उत्तरी अफ्रीकी अशांत राष्ट्रों का यूरोप की ओर होता प्रवासन है। यद्यपि भारत की भौगोलिक सीमाएं नहीं लगती हैं लेकिन भारत की भूमिका अनिवार्य

↳ . यह एक मानवीय मुद्दा है और भारत मानवाधिकारों का पक्षधर है।

↳ ~~मध्य~~ पश्चिम एशिया व उत्तरी अफ्रीकी राष्ट्रों की अशांत स्थिति पर भारत का वैश्विक सहयोग से कोई स्थायी समाधान न ढूंढ पाना एक नैतिक उत्तरदायित्वहीनता का परिणाम है।

↳ यदि भारत वैश्विक शक्ति व UNSC में स्थायी सदस्यता चाहता है तो इन

वैश्विक मुद्दों पर एक प्रभावी रणनीति होना आवश्यक है।

- यहां पर भारत को अपनी क्षमता का उपयोग कर इन शरणार्थियों को सहयोग देना चाहिए तथा संबंधित राष्ट्रों में शांति स्थापना के प्रयास करना।

भारतीय सन्दर्भ : अनुभव व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता

भारत आज विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था में शामिल है यदि कोई मानवीय संकट आता है तो भारत उस बड़ी आबादी को आर्थिक, भौतिक व मनोवैज्ञानिक सहयोग देने का सामर्थ्य रखता है।

- भारत ने अनेक शरणार्थियों को आजादी उपरांत प्रश्रय दिया है बांग्लादेशी शरणार्थी, पाकिस्तानी व हिन्दू सिख शरणार्थी (तिब्बत लोग) को न केवल प्रश्रय ही नहीं दिया बल्कि उनको यथोचित धन आर्थिक व आवश्यक सुविधाएं दी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इनके पुनर्वास को भी प्रभावित करता है यथा। तमिल शरणार्थी को श्रीलंका में पुनर्स्थापित करना।

→ हालांकि भारत अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संरक्षण कन्वेंशन का सदस्य नहीं है तथापि भारत ने हमेशा नैतिक व अपने संवैधानिक मूल्यों के आधार पर शरणार्थियों से मानवीय व्यवहार किया है

चिन्ताएं: आर्थिक बोझ, स्थानीय संसाधनों की कमी, स्थानीय आबादी के साथ संघर्ष आदि भारत की चुनौती रही हैं लेकिन फिर भी भारत ने हमेशा शरणार्थियों के मानवाधिकारों का सम्मान व संरक्षण किया है वैश्विक लाभ हेतु ही नहीं बल्कि मानवाधिकार के आधार पर भी भारत इस संकट का स्थायी समाधान चाहता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. India is endowed with an amazing variety and wealth of soft power resources. Providing examples, illustrate the utilisation of soft power in diplomatic inititives of the recent past. What are the limitations of the soft power approach in diplomacy in case of a developing country such as India?

भारत सॉफ्ट पावर (मृदु शक्ति) संसाधनों की आश्चर्यजनक विविधता एवं बहुलता से संपन्न है। उदहारण प्रस्तुत करते हुए, हाल के कूटनीतिक पहलों में सॉफ्ट पावर के उपयोग का वर्णन कीजिए। भारत जैसे किसी विकासशील देश के लिए कूटनीति में सॉफ्ट पावर एप्रोच (मृदु शक्ति उपागम) की क्या सीमाएं हैं?

सॉफ्ट पावर वह शक्ति है जो अन्य राष्ट्रों को सहयोग के लिए आकर्षित करती है, ना कि बल के प्रयोग से अथवा ... की पकड़ी में। इससे संबंधों में स्वाभाविक जुड़ाव व विश्वास आता है।

भारत एक बहु विविधता (धर्म, नस्ल, भाषा, क्षेत्र इत्यादि) के साथ साथ समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को रखता है जो इसकी सॉफ्ट पॉवर से सफलता बनाती है।

सॉफ्ट पॉवर →
- सांस्कृतिक → धर्म, भाषा (बौद्ध); सांस्कृतिक परम्पराएं
- योग, अध्यात्मवाद, भारतीय दर्शन, गीता, मेले, कार्निवल
- राजनीतिक आदर्श व मूल्य यथा, अहिंसा, लोकतंत्र
- खेल, सिनेमा, पंचशील इत्यादि।

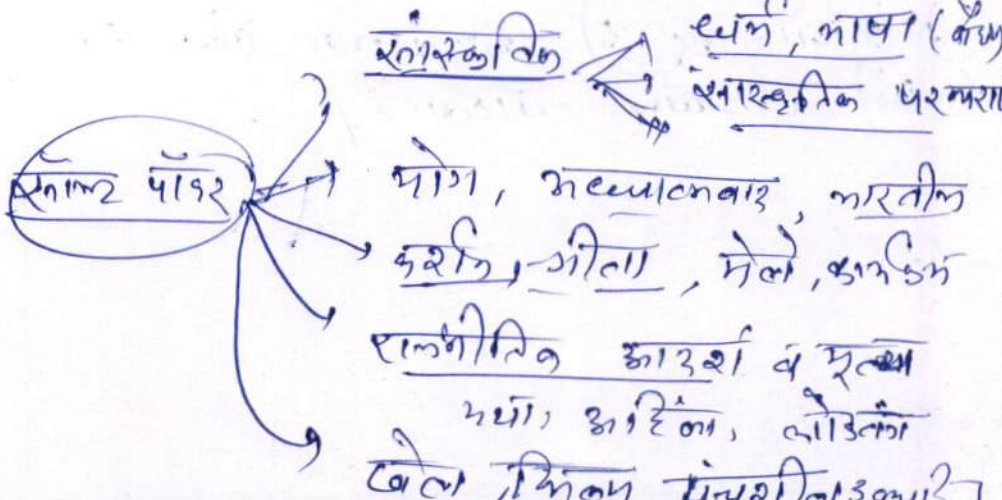

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

हाल ही में भारत व USA के बीच पारस्परिक रक्षा संबंधों को बढ़ाने में 'अप्रवासी भारतीय समुदाय' सॉफ्ट पावर ने प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है लोगों व DTTI इसी का परिणाम है
माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया आदि यात्राओं पर वहां अप्रवासियों को संबोधित कर व्यापक सहयोग की अपील की।

→ इतना ही नहीं वैश्विक मंच पर भी भारत की एक सॉफ्ट पावर ने भारत की पहचान बनाई। UN द्वारा 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करना भारत की सॉफ्ट पावर की जीत है

सीमाएं → शीघ्र परिणाम देने वाली नहीं
कई बार सांस्कृतिक भिन्नता से नकारात्मक परिणाम यथा: पाकिस्तान से संबंध
→ वहीं प्रभावी एक आर्थिक स्थिति आवश्यक

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- भारत द्वारा इसके महत्व की स्वीकार्यता
- हाल ही में इसकी शुरुआत
- अभी तक केवल अनौपचारिक प्रयोग पहली बार सक्रिय व औपचारिक प्रयोग
- भारतीय विदेश नीति में इसके विभिन्न आयामों को जोड़ना होगा।

क्योंकि आज भारत इसके बल पर काफी पहचान व सहयोग प्राप्त कर रहा है आने वाले समय में भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति इसके आर्थिक विश्व प्रभावों को बढ़ाएगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Recent upswing in Indo-Israel relations is more a reflection of evolving national interests rather than any ideological readjustment. Discuss in light of evolution of India's relations with Israel and its historical commitment to the Palestinian concerns.

भारत-इजरायल संबंधों में हाल के सुधार वस्तुतः किसी विचारधारात्मक समायोजन के बजाए विकसित होते राष्ट्रीय हित के परिणाम हैं। इजरायल के साथ भारत के संबंधों तथा फिलिस्तीन के प्रति इसके ऐतिहासिक प्रतिबद्धताओं के आलोक में चर्चा कीजिए।

भारत-इजरायल संबंध 1991 के बाद भारतीय नीति में दृष्टिगोचर होने वाले यथार्थवादी झुकाव का परिणाम है।

पहले भारत ने विचारधारात्मक आधार पर इजरायल पर प्रतिबंध लगाया हुआ था लेकिन 1991 के बाद बदलाव शुरू –

कारण
- भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु नये क्षेत्र खोजना
- प० एशिया के संभावित संसाधनों का उपयोग (ऊर्जा)
- सामरिक सुरक्षा बढ़ाने हेतु सहयोग
- तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्ति हेतु सहयोग
- विज्ञान व अंतरिक्ष में सहयोग
  RISAT 2

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें।)

ये संघ आवश्यकताओं एवं विकसित होते राष्ट्र की हैं तथा इनको पूरा करना वक्त की मांग है।

लेकिन विचारधारा के स्तर पर अभी भी भारत फिलीस्तीनी पक्ष का निर्धारण करता है तथा इजरायल की गलत कार्यवाहियों की विरोध करता है।

भारत एक पारस्परिक विश्वास व शांति के दोनों के साथ शांतिक संबंध बनाये रखना चाहता है क्योंकि विदेश नीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता है।

फिर भी भारत मानवीय मुद्दों पर हमेशा रहा है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Do you agree that Nuclear Suppliers Group's (NSG's) membership is of significant importance to India? What are the hurdles in India becoming a member of the NSG?

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एन.एस.जी.) की सदस्यता भारत के लिए अति-महत्वपूर्ण है? भारत के एन.एस.जी. का सदस्य बनने के मार्ग के कौन-सी बाधाएं हैं?

NSG की सदस्यता अति आवश्यक क्यों

↳ परमाणु अप्रसार रोकने में भारत प्रभावी भूमिका निभा सकेगा।

परमाणु सामग्री व तकनीक तक भारत की पहुंच बढ़ सकेगी

तकनीकी हस्तांतरण संभव होगा

भारत की नवीकरणीय (स्वच्छ) ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का योगदान बढ़ाने हेतु यूरेनियम आपूर्ति आवश्यक

वैश्विक मंचों पर भारत की उपस्थिति आवश्यक

↳ असैन्य परमाणु ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाना

↳ नीति निर्माण में भारत की भूमिका विशिष्टीकरण को बढ़ाएगी

↳ NSG भी भारतीय तकनीकों व नीतियों से लाभान्वित होगा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

यह ~~अति~~ महत्वपूर्ण है लेकिन अतिनहीं क्योंकि भारत की उत्तरदायी छवि व जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका के कारण देश इस में सम्मेलन हेतु निकाली भारत को परमाणु सामग्री व तकनीक उपलब्ध करा रहे हैं।

__बाधाएं__

- भारत का NPT (CTBT) पर हस्ताक्षरकर्ता न होना
- चीन जैसे राष्ट्र प्रक्रियात्मक नियमों का अनुपालन अनिवार्य मानते हैं
- नियमों में उदारता इसके लिए भारत व पाक (दोनों हेतु)

लेकिन विभिन्न देशों (38 (48 में से)) द्वारा समर्थन करना भारत की एक स्वच्छ व जिम्मेदार छवि को दिखलाता है। किन्तु भविष्य में इन बाधाओं को दूर कर लेंगे।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. India and Japan not only engage economically, the two also have strategic convergence on key issues. Explain. Also examine the issues that need to be resolved for the Indo-Japan relation to fulfill its potential.

भारत और जापान न केवल आर्थिक तौर पर सहसम्बद्ध हैं अपितु दोनों के मध्य प्रमुख मुद्दों पर रणनीतिक अभिसरण (स्ट्रेटेजिक कंवर्जेंस) भी है। व्याख्या कीजिए। साथ ही उन मुद्दों का भी परीक्षण कीजिए जिन्हें भारत-जापान संबंधों की संभावनाओं की पूर्ति के लिए सुलझाए जाने की आवश्यकता है।

आर्थिक सहसम्बद्ध:

↳ भारत — जापान

→ कच्चा माल — → औद्योगिक उत्पाद

→ निवेश अवसर — पूंजी व तकनीक

→ श्रम की कमी — सस्ती दर पर श्रम

→ विशाल बाजार — → मांग (बाजार)

रणनीतिक अभिसरण

↳ साझा दुश्मन – चीन को संतुलित करना

↳ मेरीटाइम सुरक्षा – पायरेटों का खतरा

↳ दोनों USA के सहयोगी – इंडो पैसिफिक प्रशांत – हिन्द सहयोग को

↳ रणनीतिक साझेदारी बढ़ावा

↳ भौगोलिक व तकनीक उपलब्धता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुलझाने योग्य मुद्दे

- FTA को बढ़ावा देना
- असैन्य परमाणु समझौते का क्रियान्वयन न होना
- जापानी विदेश के लिए भारत में सुरक्षा व शीघ्र अनुमति की कमी
- तकनीकी हस्तांतरण सरल बनाना
- अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ाना
- मेरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देना।
- सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना।

इत्यादि

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Though there are unresolved issues between the three, the Russia-India-China trilateral is indispensable to construct a multipolar world. Analyse.

यद्यपि तीनों (रूस-भारत-चीन) के बीच अनसुलझे मुद्दे विद्यमान हैं तथापि रूस-भारत-चीन त्रिकोण बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। विश्लेषण कीजिए।

अनसुलझे विवाद

रूस - चीन
- सीमा विवाद
- राजनीतिक विचारधारा (साम्यवाद पर ही टकराव)
- सीमों पर कब्जे को लेकर विवाद
- वैश्विक मंचों पर प्रतिस्पर्धी स्पर्धा
- मुक्त व्यापार न होना

चीन भारत
- सीमा विवाद
- चीनी घेराव नीति
- आर्थिक क्षेत्र में भारत का व्यापार घाटा
- चीनी लोकतंत्र की कमी (मानवीय अधिकारों विकास की न होना)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत-रूस . हाल में बढ़ती कुछ दूरियां
अन्यथा प्रकाश विचारणीय

क्योंकि

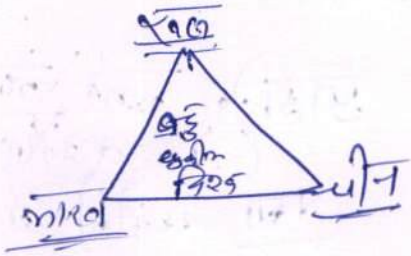

↳ विश्व की बड़ी आबादी के संरक्षक
↳ चीन व भारत जनांकिकीय लाभांश के दौर में
↳ तीनों की भौगोलिक नजदीकी
↳ तीनों उभरती अर्थव्यवस्थाएं व विभिन्न मंचों पर समान विचारधाराएं यथा BRICS, G-20, Brics NDB, AIIB इत्यादि
↳ बढ़ता घरेलू बाजार व मांग
↳ पश्चिम एशिया में बढ़ती भूमिका
- वैश्विक मुद्दों पर भूमिका - यथा रोहिंग्या, ईरान etc

VISION IAS™
Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आज के विश्व में स्वतंत्र कार्य नीति एक देश पर नहीं हो सकती है। बहुध्रुवीयता आवश्यक भी है और अधिकांश की ताकि संतुलित विकास हो।

- रूस → प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन (तेल व गैस) तथा तकनीकी उन्नति
- चीन – विनिर्माण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता
- भारत – सेवा क्षेत्र की उत्कृष्टता

⇓

तीनों की संभावना एक साथ मिलकर विकास लायेंगी।

Call us : 9650617807, 9968029039
Blog : www.visionias.wordpress.com
Visit us : www.visionias.in
Email : ajay.visionias@gmail.com